International Journal of Applied Research 2015; 1(10): 125-127

ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 5.2
IJAR 2015; 1(10): 125-127
www.allresearchjournal.com
Received: 12-07-2015
Accepted: 20-08-2015

डॉ0 विनोद कुमार यादव
प्राध्यापक, वाणिज्य विभाग,
कालीचरण पी0जी0 कालेज, लखनऊ

Correspondence
डॉ0 विनोद कुमार यादव
प्राध्यापक, वाणिज्य विभाग,
कालीचरण पी0जी0 कालेज, लखनऊ

डिजिटल इण्डिया कार्यक्रमं

डॉ0 विनोद कुमार यादव

शोध सारांश
डिजिटल इण्डिया एक ऐसा कार्यक्रम है यह कार्यक्रम भारत देश में ई0 क्रान्ति (इलेक्ट्रानिक क्रान्ति) के द्वारा समाज में परिवर्तन लाने के लिए है इस कार्यक्रम को इलेक्ट्रानिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से कार्यक्रम को संचालित किया जायेगा इसके अन्तर्गत सभी को कम्प्यूटर एवं इण्टरनेट के बारे में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा तथा सभी प्रकार के प्रमाण–पत्रों को एवं सरकारी दस्तावेजों को ऑनलाइन सुविधाओं के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है इसके द्वारा सामान्य एवं साधारण लोगों को सरकारी सेवायें कम समय में उपलब्ध हो जायेंगी इसका मुख्य उद्देश्य सशक्त समाज और ज्ञानवर्धक अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है।

डिजिटल इण्डिया कार्यक्रम को भारत सरकार ने देश में ई0 क्रान्ति (इलेक्ट्रानिक क्रान्ति) के रूप में जाग्रत करने के लिए महात्वाकांक्षी योजना ''डिजिटल इण्डिया कार्यक्रम'' को प्रारम्भ किया गया है। इस कार्यक्रम पर 1.13 लाख करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे। भारत सरकार के इलेक्ट्रानिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से कार्यक्रम को संचालित किया जायेगा। यह डिजिटल इण्डिया कार्यक्रम 20 अगस्त, 2014 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में अनुमति प्रदान की गयी। यह कार्यक्रम भारत को डिजिटल स्वरूप एवं सशक्त समाज और ज्ञानवर्धक अर्थव्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए है।

अतः डिजिटल इण्डिया कार्यक्रम को वर्ष 2014 से 2018 तक चरणबद्ध रूप से क्रियान्वयन किया जायेगा, जिसके अन्तर्गत सभी को कम्प्यूटर एवं इण्टरनेट के बारे में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा तथा सरकारी सेवाओं को समाज के सभी लोगों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध होगी। इससे किसानों की जमीन/भूमि के दस्तावेज से लेकर ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और अन्य कई तरह के प्रमाण–पत्रों को एवं सरकारी दस्तावेजों को ऑनलाइन सुविधाओं के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इसके द्वारा सामान्य एवं साधारण लोगों को सरकारी सेवायें कम समय में उपलब्ध हो जायेंगी तथा इससे सरकारी प्रतिनिधियों एवं कर्मचारियों के दायित्व और जवाबदेही को सुनिश्चित करना भी आसान हो जायेगा।

देश में ई–क्रान्ति के आ जाने के कारण डिजिटल इण्डिया कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी लोगों को कम्प्यूटर का प्रशिक्षण भी प्रदान किया जायेगा, जिससे साधारण एवं सामान्य लोगों को कम्प्यूटर एवं इण्टरनेट के माध्यम से अपना कार्य समय से कर सके। इसके साथ ही देश में 2019 तक सभी ढाई लाख ग्राम पंचायतों को ब्राडबैण्ड सेवा के माध्यम से जोड़ा जायेगा तथा स्कूल, कालेज/विद्यालय

एवं विश्वविद्यालयों में इण्टरनेट, वाई–फाई की सुविधा प्रदान की जायेगी। इसके अन्तर्गत इण्टरनेट की उच्च स्पीड के साथ किसी एवं कहीं पर भी मोबाइल सम्पर्क सुविधाएं प्राप्त होगी। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के नागरिकों को डिजिटल रूप में सुविधा प्रदान करके सशक्त देश बनाना है।

अतः डिजिटल इण्डिया कार्यक्रम को संचालन करने के लिए सरकार ई–गवर्नेंस (e-governance) परियोजना तथा राष्ट्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी केन्द्र का पुनर्गठन करेगी। जोकि सरकारी विभागों में इन्फार्मेसन टेक्नालॉजी की सुविधायें प्रदान की जायेंगी। अतः सरकार कम से कम दस प्रमुख मंत्रालयों के विभागों में मुख्य सूचना अधिकारी का पद सृजित करेगी तथा डिजिटल इण्डिया कार्यक्रम की देख–रेख के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक समिति करेगी। इस डिजिटल इण्डिया कार्यक्रम के सुदृढ़ प्रभावकारी संचालन के लिए सलाहकार समूह बनाया जायेगा। इस समूह की अध्यक्षता सरकार के केन्द्रीय संचार एवं सूचना मंत्री होंगे।

अतः यह डिजिटल इण्डिया कार्यक्रम लोगों को विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी के द्वारा जोड़ने का कार्य करता है, जिससे लोगों को सरकार की सभी योजनाओं एवं सुविधाओं को कम समय में उपलब्ध हो जायेंगी और इससे सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और असैधान्तिक क्रिया–कलापों पर रोक लगेगी। इससे सरकार शासन, अनुशासन, कार्यप्रणाली, रूप–रंग, माध्यम और कार्यशैली आदि सभी में परिवर्ततन आयेगा। इस डिजिटल इण्डिया कार्यक्रम के द्वारा सरकार ने जन–जन को जोड़ने और देश की प्रगति में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए इस कार्यक्रम को प्रारम्भ किया है। यह कार्यक्रम अनेक विभागों का मिला–जुला ?अम्ब्रेला स्वरूप कार्यक्रम है। यह एक एकल खिड़की अर्थात् सिंगल विण्डों के रूप में कार्य करेगा। इसके द्वारा सम्पूर्ण भारत देश को, उन सभी गाँव एवं ग्रामीण क्षेत्रों को हाई–स्पीड इण्टरनेट एवं इलेक्ट्रॉनिक सुविधाओं के माध्यम से जोड़कर एक सशक्त समाज बनाकर ज्ञान–विज्ञान से आधारित अर्थव्यवस्था के स्वरूप में परिवर्तित करने का कार्य करेगा।

डिजिटल इण्डिया

डिजिटल इण्डिया एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है, जिसके अन्तर्गत देश के सभी कोने–कोने को तथा जन–जन को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जोड़ करके डिजिटल सशक्त एवं संवृद्धि समाज का निर्माण करना है और उसे ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के स्वरूप में परिवर्तित करना है।

अतः डिजिटल इण्डिया कार्यक्रम से भारत को डिजिटल सशक्त समाज और ज्ञानवर्धक अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करने के लिए किया गया है तथा 7–अगस्त 2014 को डिजिटल इण्डिया कार्यक्रम के बारे में प्रधानमंत्री की बैठक के दौरान कार्यक्रम के स्वरूप की रूपरेखा (डिजाइन) पर लिए गये निर्णय तथा इसके द्वारा सरकार के मुख्य निर्णयों और सभी मंत्रालयों के कार्यों, अनुदेशों एवं योजनाओं को देश के सभी कोने–कोने तक वृहत रूप में जानकारी एवं सूचनायें प्रदान करने के लिए उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। यह कार्यक्रम इलेक्ट्रॉनिक और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विभागों की परिकल्पना का स्वरूप है।

उद्देश्य

डिजिटल इण्डिया कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश को डिजिटल सशक्त समाज और ज्ञान पूर्ण अर्थव्यवस्था में प्रदर्शित करना है। इस कार्यक्रम का आरम्भ वर्ष 2014 से 2018 तक चरणबद्ध ढंग से क्रियान्वित किया जायेगा। डिजिटल इण्डिया कार्यक्रम की प्रकृति रूपांतकारी है। इससे यह सुनिश्चित हो जायेगा कि सरकारी सेवायें, सुविधाओं एवं योजनाओं को नागरिकों तक इलेक्ट्रानिक रूप में उपलब्ध हो सके। अतः सरकार की सेवाओं एवं सुविधाओं को इलेक्ट्रानिक स्वरूप में प्रदान करने के लिए तथा इसका सार्वजनिक जवाबदेही को बढ़ाया जा सकेगा। जबकि अधिकांश ई–गवर्नेन्स परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों के लिए आर्थिक सहायता केन्द्र एवं राज्य सरकारों के सम्बंधित मंत्रालयों, विभागों के बजटीय प्राविधानों के द्वारा होता है। डिजिटल इण्डिया कार्यक्रम के लिए तथा विभिन्न परियोजनाओं के लिए फण्ड की आवश्यकता का आंकलन सम्बंधित नोडल मंत्रालय का विभाग लगायेगा।

डिजिटल इण्डिया कार्यक्रम का विजन एवं क्षेत्र

सभी नागरिक के लिए सुविधा के रूप में बुनियादी स्वरूप

- मुख्य सुविधा के रूप में हाई स्पीड इंटरनेट सभी ग्राम पंचायतों में उपलब्ध कराया जाएगा।
- इसके द्वारा अनोखी, आजीवन, ऑनलाइन और प्रमाणन योग्य डिजिटल पहचान इत्यादि होगी।
- मोबाइल फोन और बैंक एकाउंट व्यक्तिगत स्तर पर डिजिटल और वित्तीय स्वरूप में भागीदारी में समर्थ एवं सहायक होगा।
- स्थानीय स्तर पर सामान्य सेवाओं को केन्द्र तक पहुँचाने का कार्य।
- सार्वजनिक जनसमूह में साक्षा करने योग्य निजी स्थान उपल्बध करना।
- देश में सुरक्षित साइबर स्पेस की सेवाएं प्रदान करना।

ई–गवर्नेन्स और माँग की सेवाए

- प्रत्येक नागरिक को आसान एवं सिंगल विंडो एक्सेस उपलबध कराने के लिए विभागों या अधिकार क्षेत्रों तक निर्बाध समांकलन करना।
- ऑनलाइन और मोबाइल प्लेटफार्म से रीयल टाइम में सरकारी सेवाएं उपलब्ध करना।
- सुगम पहुँच सुनिश्चित करने के लिए सभी नागरिकों को क्लाउड पर उपलब्ध कराने का अधिकार प्रदान करना।
- इलेक्ट्रॉनिक और कैशलेस वित्तीय लेनदेन की सुविधा प्रदान करना।

डिजिटल सशक्त नागरिक

- सभी नागरिकों को डिजिटल साक्षर बनाना और ई–लर्निंग को बढ़ाना।
- सभी डिजिटल संसाधन सभी को सुगम–सहज उपलब्ध कराना।
- सभी सरकारी कागजात, प्रमाण–पत्र, योजनाओं को क्लाउड पर उपलब्ध कराए जाएंगे।
- भारतीय भाषाओं में डिजिटल संसाधन एवं सेवाओं की उपलब्धता।
- डिजिटल इण्डिया का वृहत कार्यक्षेत्र।
- भारत के ज्ञान को भविष्य के लिए पूर्ण रूप में तैयार करना।
- बदलते परिवेश के लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी को केन्द्रीय स्तर पर रखना।

डिजिटल इण्डिया कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य

- ब्राडबैंड हाइवेज परिपथ उपलब्ध करना।
- मोबाइल कनेक्टिविटी की सेवा सबको सुगम–सुलभ हो सके।
- सार्वजनिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम को बढ़ाना।
- ई–गवर्नेन्स प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकार की कार्य प्रणाली को सुधारना।
- ई–क्रांति सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक सुपुर्दगी प्रदान करना।
- सभी के लिए जानकारी उपलब्ध करना।
- इलेक्ट्रॉनिक्स विर्निमाण करना।
- रोजगार उपलब्ध करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ाना।

- अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम्स का संचालन करना।

एनआईसी के ई–ग्रीटिंग्स पोर्टल का आरम्भ

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के द्वारा 14 अगस्त 2014 को ई–ग्रीटिंग्स कार्यक्रम पोर्टल का उद्घाटन किया जिसे भारत सरकार के डिजिटल इण्डिया कार्यक्रम के रूप में एनआईसी ने विकसित किया है। इसकी डिजाइन के वर्तमान कैटलॉग को विशेष रूप में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ई–ग्रीटिंग्स के रूप में भेजने के लिए डिजाइन किया गया है।

अतः सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विभाग द्वारा यह नवाचार का आरम्भ सरकार की भारत में उचित सूचना प्रौद्योगिकी की क्रांति सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता के क्रम का एक अंश है। 15 अगस्त पर ई–ग्रीटिंग्स को जनता की भागीदारी के माध्यम से देश के लोगों के सहयोग से उचित दिशा में बढ़ाए गए कार्य वं योजना के रूप में तैयार किया गया है। पोर्टल का उद्देश्य सरकारी अधिकारियों और एजेंसियों द्वारा अपने सहयोगियों और मित्रों को शुभकामनाएं भेजने के एक समकालिक और यह पर्यावरण सहायक के रुप में प्रोत्साहित करना है। इस पोर्टल से उपभोक्ता इस अवसर पर उपलब्ध अनेक नमूनों में से अपनी पसन्द के संदेश भेज सकते हैं।

ई–ग्रीटिंग्स पोर्टल विशिष्ट है क्योंकि स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं के लिए अधिकांश डिजाइन अभी हाल में शुरू किए गए माइगाँव पोर्टल के तहत जनता की भागीदारी में तैयार किया गया है। पोर्टल पर लगभग 20 चुनिंदा डिजाइन उपलब्ध हैं। अतः उपयोगकर्ता http://egreetings.india.gov.in लिंक करके पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं।

डिजिटल इण्डिया कार्यक्रम का विजन 2020

- सभी को सुगम–सुलभ ढाई लाख गांवों में ब्रॉड बैंड सम्पर्क की सुविधा।
- वर्ष 2020 तक नेट जीरो आयात करना।
- चार लाख पब्लिक इंटरनेट उपलब्धता केन्द्र।
- ढाई लाख स्कूलों एवं सभी विश्वविद्यालयों में वाई–फाई एवं नागरिकों के लिए सार्वजनिक वाई–फाई हॉटस्पॉट्स की सुविधा।
- डिजिटल समावेश हेतु आईटी, टेलीकॉम एवं इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में रोजगार हेतु 1.7 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षत किया जायेगा।
- रोजगार के सृजन से 1.7 करोड़ युवाओं को प्रत्यक्ष एवं कम से कम 8.5 करोड़ युवाओं को अप्रत्यक्ष रूप से काम मिलेगा।
- ई–गवर्नेंस एवं ई–सेवाएं के द्वारा सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा, बैकिंग क्षेत्र की सेवाओं में सूचना तकनीक उपयोग में भारत का वर्चस्व।

डिजिटल इण्डिया कार्यक्रम के द्वारा नवीन तकनीकी एवं ज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकेगी। इससे भारत के लगभग 98 प्रतिशत गाँवों को उन सभी सुविधाओं की जानकारी हो सकेगी, जिसको सरकार के द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है।

निष्कर्ष

डिजिटल इण्डिया कार्यक्रम भारत देश में ई0 क्रान्ति (इलेक्ट्रानिक क्रान्ति) के द्वारा समाज में परिवर्तन एवं नवीन तकनीकी ज्ञान प्राप्त होगा इस कार्यक्रम से भारत के गाँवों को उन सभी सुविधाओं एवं योजनाओ की जानकारी हो सकेगी इसके अन्तर्गत सभी को कम्प्यूटर एवं इण्टरनेट के बारे में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा तथा इससे 1.7 करोड़ युवाओं को प्रत्यक्ष एवं कम से कम 8.5 करोड़ युवाओं को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा अतः ई–गवर्नेंस एवं ई–सेवाओं के द्वारा सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा, बैकिंग क्षेत्र की सेवाओं में सूचना तकनीक उपयोग में भारत का वर्चस्व होगा तथा सभी प्रकार के प्रमाण–पत्रों को एवं सरकारी दस्तावेजों को ऑनलाइन सुविधाओं के द्वारा प्रदान किया जायेगा और सामान्यः लोगों को सरकारी सेवायें कम समय में उपलब्ध हो जायेंगी इसका मुख्य उद्देश्य सशक्त एवं संवृद्धि समाज का निर्माण करना है।

सन्दर्भ सूची ¼Reference½

1. प्रतियोगिता दर्पण अतिरिक्तांक
2. Economic Times Magazine, New Delhi.
3. Yojan, (English) Published by Yojna Bhawan Parliament street New Delhi.
4. Economic times news paper
5. Times of india news paper
6. The hindi Danik Jagran news paper
7. Indian express news paper
8. Business india Magazine
9. Various websitè